INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES

ISSN 2277 – 9809 (online)
ISSN 2348 - 9359 (Print)

An Internationally Indexed Peer Reviewed & Refereed Journal

www.IRJMSH.com
www.isarasolutions.com

Published by iSaRa Solutions

भारतीय समाज के विकास में नागरिक शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व

दीपक
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

राष्ट्रीय स्तर पर नागरिक शिक्षा की प्रमुखता

शिक्षा व्यक्ति के विकास और समाज की सम्पन्नता का एक मुख्य साध्न है। व्यक्ति और समाज का विकास सदैव एक राष्ट्र के समक्ष तत्कालीन उद्देश्य के रूप में विध्मान रहता है। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोई राष्ट्र भावी पीढ़ी के निर्माण में शिक्षा व्यवस्था को अपना आधर बनाता है। भारत एक लोकतांत्रिक, पंथनिरपेक्ष और बहुसंस्कृतिवादी देश है अतः इन मूल्यों की प्राप्ति तब संभव हो सकती है जब नागरिकों को इनके महत्व और प्रांसगिकता के बारे में परिचित कराया जाये। इसलिए नागरिकता की शिक्षा को आधुनिक भारतीय शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक तत्व के रूप में रेखांकित किया गया है। समाज में सहनशीलता, संस्कृति का सम्मान, वातावरण का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के शोषण की समाप्ति का प्रचार और जागरुकता नागरिक शिक्षा द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है इसलिए नागरिक शिक्षा का महत्व आज सभी राष्ट्रों के मध्य में स्थापित है। भारतीय पाठ्यपुस्तकों में नागरिक शिक्षा की विशेषताओं को 1975 ई. से रेखांकित किया जा सकता है और इसी समय से इसमें सक्रिय नागरिकों के विकास की आवश्यकता को महसूस किया जाने लगा।[1] 'राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 1975 ने यह सुझाव दिया कि 'भारतीय नागरिक भविष्य के लिए तैयार हो जो समुदाय, राज्य और देश में वृहत स्तर पर सहभागी बन सके'। समाजिक विज्ञान के शिक्षण में आलोचनात्मक पक्ष की उपयोगिता को चिन्हित किया गया ताकि सचेत नागरिकों का निर्माण सुनिश्चित किया जा सके जो अपने अध्किारों और कर्तव्यों का पालन सक्रियता से करें जिसके पफलस्वरूप भारतीय संविधन के सि(ांतो को प्राप्त करने में सरलता होगी।[2] करीब एक दशक से अध्कि समय बाद 'विद्यालयी पाठ्यचर्चा की रूपरेखा–2000' का निर्माण नई राजनीतिक परिस्थितियों के मध्य हुआ जिसने नागरिकता की शिक्षा को 'राष्ट्रीय पहचान वृ(' के आवश्यक विषय वस्तु के रूप में परिभाषित किया जिसका उद्देश्य भारतीय लोगों में मौलिक कर्तव्यों और भारतीय रूपी पहचान होने के महत्व को स्थापित करना था।[3] 'विद्यालयी पाठ्यचर्या 1975' ने यह सुझाव दिया कि नागरिक शिक्षा के आधर स्वरूप मानववाद, ध्र्मनिरपेक्षवाद, समाज और लोकतंत्रावाद को इसका आधर बनाया जाये जो नागरिकों को न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में प्रोत्साहित करेगा तथा समाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देगा इसके अतिरिक्त हिंसा को न्यून करने में मदद करेगा जिसके पफलस्वरूप सम्पन्न और शांतिपूर्ण समाज की स्थापना होगी ख्छब्म्त्ज्ए 1975रू19,ण्द्य कक्षा शिक्षण में सामाजिक विज्ञान का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को प्रोत्साहित करना है ताकि वह आर्थिक और सामाजिक पुर्ननिर्माण में सहभागी बन सकें। शिक्षा मानीवय संसाध्नो के विकास का एक शक्तिशाली यन्त्रा है जिसकी सहायता से मानवीय उ(ार प्रक्रिया स्वरूप सरलता से हो सकता है। इस विचार को ही सामाजिक विज्ञान के वृहत लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है जो राष्ट्र की आकांक्षाओं के अनुरुप परिलक्षित होता है ;छब्म्त्ज्ए 1988रू3द्ध 'राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2005' के अनुसार– सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य आलोचनात्मक नागरिकता का विकास करना होना चाहिए जो संविधन के मूल्यों की ओर उन्मुख हो। सामाजिक विज्ञान की रूपरेखा आलोचनात्मक समझ को बढ़ावा दे जिससे समाज में न्याय और शांति स्थापना को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त समाजिक खोज ;म्दुनपतलद्ध को वैज्ञानिकता के साथ जोड़े जो पराम्परागत ढ़ांचो को चुनौती दे सके और विद्यार्थियों में शंका, नैतिकता तथा बौ(कि शक्ति को उत्पन्न करें। ऐसा करने से जो समाजिक ताकतें उन्हें नुकसान पहुंचाती है वह उनके विरु(सचेत, जागरुक तथा सजग हो जायेंगे जो संवैधनिक मूल्यों की स्थापना होगी।[4] राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा ;2005:49द्ध ने यह सुझाव दिया है कि सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या की विषय वस्तु ;ब्वदजमदजद्ध का आधर इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्रा को मिलाकर बनाया जाये और इसके माध्यम से विद्यार्थियों को विभिन्न संदर्भो के साथ जोड़ने का प्रयास करना चाहिए जैसे निर्ध्नता, अशिक्षा, बाल–मजदूरी, वर्ग, जाति, लिंग और वातावरण से जुड़ी संकल्पनाओ के साथ। इस तरह से सामाजिक विज्ञान युवा विद्यार्थियों को राष्ट्र से सम्बन्ध्ति मुद्दों के साथ जोड़ सकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है जो ध्र्मनिरपेक्ष मूल्यों और भारतीय समाज को मजबूत करेगा। विद्यालय में बहुत सी बातें सिखाई जाती हैं परन्तु नागरिक शास्त्रा विषय मूल रूप से राज्य की विशेषताओं के

[1] National Council for Research & Training (NCERT), 'The Curriculum for Ten Year School; A Frame work', New Delhi, 1975
[2] NCERT,'National Curriculum for Elementrary and Secondary Edu.: A Fraemwork (NCESE), New Delhi, 1988.
[3]NCERT'National Curruculum Fraemework for School Education', New Delhi, 2000.
[4] NCERT, 'National Curriculum Framework – 2005', New Delhi, pp.48.

साथ जुड़ा होता है। यह समतलीय रूप से राज्य के अजेन्डा से और राज्य की शक्ति संरचना से प्रभावित होता रहता है। नागरिकशास्त्रा विषय राज्य द्वारा निर्देशित होता है।

अमेरिका में नागरिकशास्त्रा विषय का आधुनिक रूप नजर आता है जिसमें जनसमुदाय को सार्वजनिक जीवन में भागीदारी के लिए निर्देशित किया गया है। अमेरिका में नागकिरता की शिक्षा गणतंत्राीय लोकतंत्रा को स्थापित करने के लिए प्रारम्भ की गई। इसका उद्देश्य अमेरिकी लोगों को सरकार की कार्यप्रणाली से अवगत कराना था।[5] इसके अतिरिक्त जन मानस में सहभागिता और सामाजिक, आर्थिक विषयों के सन्दर्भ में जागरुकता का प्रचार करना था।

जन समुदाय को राज्य की संस्थाओं के प्रति उचित व्यवहार को निर्देशित करने का विषय एक मुख्य तत्व के तौर पर वैश्विक स्तर पर उभरा। इग्लैण्ड में भी 'नागरिकता की शिक्षा' राज्य के समक्ष एक प्रमुख संदर्भ के रूप में उभर कर सामने आयी। इसमें नागरिकता की शिक्षा के अन्तर्गत राज्य की कार्यप्रणाली और भूमिका की व्याख्या की गई, जिसे इग्लैंण्ड के विद्यालयों में प्रोत्साहित किया गया। इस संदर्भ को ही 19वीं शताब्दी के अन्त में 'नागरिक शास्त्रा' ;ब्पअपबेद्ध का नाम दिया गया।[6]

अमेरिका और इग्लैण्ड दोनों ही देशो में नागरिकता की शिक्षा का महत्व स्वीकार किया गया है। दोनो ही देश उदारवादी लोकतंत्रा के परिचालक हैं। इसलिए वह नागरिकों को अध्किार और कर्तव्यों के प्रति जागरुकता को आवश्यक मानते है और वर्ग तथा जाति के भेदभाव को समाप्त करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। लेकिन अभिजन वर्ग को स्थापित करने के लिए दोनों ही राज्य की कार्यप्रणाली को प्रभावित करने के लिए तत्पर रहते हैं।

भारत में नागरिकता की शिक्षा का स्वरूप ब्रिटिश शासन ने निर्धारित किया था जिसकी राजनैतिक शिक्षा की संकलपना ही प्रतिबंध्ति रूप में प्रकट होती है। इसके अन्तर्गत केवल राज्य की नीतियों और कार्यप्रणाली को सूक्ष्म रूप से प्रस्तुत किया गया था ताकि भारतीय लोग ब्रिटिश उपनिवेशवाद का विश्लेषण न कर सके। स्वतंत्राता पश्चात् भी भारतीय राज्य में नागरिकता की शिक्षा का स्तर उपनिवेशवादी प्रवृत्तियों की तरह ही अपनाया गया। 1990 के मध्य तक एन.सी.ई.आर.टी ;छब्म्त्ज्द्ध की नागरिकशास्त्रा की पुस्तकों का आधर केवल शासन के सि(ांतों और सरकार के स्वरूप की व्याख्या करना था जो राज्य केन्द्रित समाजवाद पर आधरित था ;डंकंदए 1995द्ध।

किंतु राज्य से अलग कुछ गैर सरकारी संगठन भी उभरे जैसे मध्य प्रदेश में एकलव्य। इस संगठन द्वारा रचित नागरिकशास्त्रा पाठ्यपुस्तकों की विषयवस्तु ने नये और भिन्न प्रकार की दृष्टि को राज्य के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया है। इसके अनुसार लोगों में भिन्न प्रकार की आवाज़े और दबाव समूह हैं जो राज्य के सक्रिय नागरिक हैं ना कि असक्रिय स्वीकार्यकर्ता। वे जानते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है। इस संदर्भ में उन्हें सरकार द्वारा बताये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नागरिकशास्त्रा की पाठयपुस्तको द्वारा वृहत स्तर पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि कैसे राज्य की कार्यशैली सभी व्यक्तियों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन से जुड़ी है। एकलव्य द्वारा निर्देशित इस विषय–वस्तु का कार्य सक्रिय नागरिकता का विकास करना है जो प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर पर इसकी महत्ता को प्रदर्शित करता है। इसलिए कक्षा–6 की पाठ्यपुस्तकों में अन्तनिर्भरता को मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक बताया है।[7] कक्षा–7 की पाठ्यपुस्तकें भी नागरिको में उद्यौगिकरण के विकास को मानव विकास की आवश्यक शर्त के रूप में प्रदर्शित करती हैं। राज्य ने आर्थिक प्रक्रिया को नागरिक विकास के लिए आवश्यक तत्व के रूप में पेश किया है।[8] वही कक्षा–8 की पाठ्यपुस्तकों में मजदूरों के समक्ष प्रस्तुत चुनौतिपूर्ण कार्य को उनकी जीवनशैली के रूप में दिखाया गया है ताकि नागरिक इन सन्दर्भो में जागरुक हो सकें।[9]

नागरिकों के लिए उत्तम और आवश्यक शिक्षा का प्रबन्ध् करना राज्य का अनिवार्य कार्य है। पोलो प्रफेरे ;च्नसव थ्तपमतमद्ध ने राष्ट्र विकास के लिए नागरिको के मध्य 'संवाद' ;ब्वउउनदपबंजपवदद्ध की भूमिका को आवश्यक माना है और अन्तः व्यक्ति ;प्दजमत.चमतेवदंसद्ध वार्तालाप को इसके एक तत्व के रूप में स्वीकार किया है। प्रफेरे नागरिको में आलोचनात्मकता को बढ़ावा देने के पक्ष में थे क्योंकि इससे ही उन पर हो रहे शोषण और अत्याचार को वे खत्म कर सकते थे। नागरिक शिक्षा को वह शोषण के विरु(एक साध्न के रूप में देखते थे। व्यक्ति शोषण के विरु(तभी आवाज़ उठा सकता है जब वह शिक्षित हो और संवाद को बढ़ावा दे ताकि वह अपनी बात कह सके। प्रफेरे ने राज्य को एक बैकिंग प्रणाली के रूप में व्याखित किया है जिसमें बैंक की तरह सभी केवल कामों में व्यस्त रहते है और अपने पफायदों के लिए कार्य करते हैं जिससे समाज में निम्न वर्गो के शोषण को बढ़ावा मिलता है। अतः इस व्यवस्था को समाप्त करना होगा, आवाज़ उठानी होगी तभी शोषण से मुक्ति मिल सकती है। यह समाज में अलोचनात्मक, विश्लेषण, स्वंय विश्लेषण तथा संस्कृति विश्लेषण को आवश्यक मानते है जो समाज और बौ(िक विकास के लिए आवश्यक है। इस प्रकार पोलो प्रफेरे के विचार नागरिक शिक्षा को

[5] Nietz, J.A. 'Old Textbooks: Spelling, Grammar, Reading, Arithmetic, Geography, American History, Civil Government, Physiology, Penmanship, Art, Music, As taught in the common Schools from Colonial days to 1900. Pittsburgh:Pittsburgh University Press. 1961.

[6] Heater, Derek. 'The History of Citizenship Education in England', The Curriculum Journal, 12(1): 123--130, 2001

[7] Eklavya. Samajik Adhyan : Kaksha 6. Bhopal: Madhya Pradesh Textbook Corporation, 1993.

[8] Eklavya. Samajik Adhyan : Kaksha 7. Bhopal: M.P. Text book corporation, 1994a.

[9] Eklavya. Samajik Adhyan : Kaksha 8. Bhopal: M.P. Text book corporation, 1994b.

राष्ट्रीय विकास की एक आवश्यकता के रूप में प्रस्तुत करते है। राज्य की क्रियाओं में भागीदारी करना, अपने विचार देना जो समाज के दूसरे लोगों को भी जागरुक करेगें। ऐसा करके ही संरचनात्मक समाज और देश का निर्माण किया जा सकता है।

आज भारत में भी इस प्रकार की शिक्षा को अपनाने के लिए 'राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2005' द्वारा कदम उठाये गये हैं। इसमें भारतीय नागरिकों में आचोनात्मकता, सचेतता और विश्लेषण करने की उनकी क्षमता को बढ़ाने पर अपने सुझाव दिये गये हैं ताकि उनके मध्य लिंग, जाति, वर्ग, वातावरण, आदिवासी, धर्मनिर्पेक्षता, लोकतंत्रा, मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, समानता, स्वतंत्राता, संसाधनो का समुचित उपयोग और जनसंख्या से सम्बन्धित समस्याओं के सन्दर्भ में अपनी समझ को विकसित कर सकें।[10] भारत में इन समस्याओं को सुलझाने का साध्न नागरिक शिक्षा और सम्बन्धित पाठ्यचर्या के विकास को बनाया गया है। भावी नागरिकों से राज्य यह अपेक्षा कर रहा है कि वह देश के विकास में भागीदार बने और राष्ट्र से जुड़े संवेदनशील तथ्यों के प्रति जागरुक हों। तभी हम देश के समाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौतिक, मानसिक, बौ(कि, मानवीय और राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकेगें।

किसी राष्ट्र के समक्ष अपने नागरिकों में उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार का विकास करना एक प्रमुख चुनौती होती है। स्वतंत्राता प्राप्ति के पश्चात् भारत ने अपने आप को एक लोकतांत्रिक देश के रूप में स्वीकार किया जिसके कारण नागरिकों के मध्य उत्तरदायित्व व्यवहार को आवश्यक माना गया। इसलिए शिक्षा व्यवस्था को एक साध्न के तौर पर देखा गया ताकि वह नागरिकों के मध्य सहनशीलता, सक्रियता और मानवीयता के प्रति आदर जैसे मूल्यों का संचार कर सके। भारतीय राष्ट्र ने नागरिकता की शिक्षा को देश के विकास के लिए एक आवश्यक तत्व के रूप में स्वीकार किया है क्योंकि नागरिकों के व्यवहार और शिक्षा का स्तर ही उस राष्ट्र के स्वरूप और स्थिति को निर्धरित करता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने इस उद्देश्य की पूर्ती हेतु ही कुछ बिन्दुओं पर प्रकाश डाला है जैसे–

- व्यक्तित्व का विकास और
- नेतृत्व की शिक्षा[11]

व्यक्तित्व के विकास के लिए खेल–कूद, कला, नृत्य तथा नाटक को आवश्यक माना जो विद्यार्थियों के मध्य संरचनात्मक विकास को प्रोत्साहित करने में मददगार होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था बिना सक्रिय नेतृत्वकारी व्यक्तित्व के मंद हो जायेगी। समाज का नेतृत्व करना और उनमें इसके विकास को रेखांकित करना लोकतंत्रा के विकास की आवश्यक मांग है। इसके माध्यम से व्यक्ति और समाज को एक साथ लाया जा सकता है और उनके मध्य सहमति को स्थापित किया जा सकता है।

किसी राष्ट्र के लिए 'नागरिकता की शिक्षा' की प्रमुखता को निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति के रूप में रेखांकित कर सकते हैं।

- **लोकतांत्रिक मूल्य–** लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों की सहभागिता और सहमति को एक आवश्यक तत्व के रूप में रेखांकित करना जो समाज में तनाव और विवादों को कम करने में मदद करती है तथा नागरिको के मध्य सहयोगपूर्ण वातावरण के निर्माण में सहायक होती है। इसके अन्तर्गत विभिन्न मतो, विचारो और सुझावों के मध्य सांमजस्य स्थापित किया जाता है।
- **बहुसंस्कृतिवाद–** आज समस्त विश्व एक वैश्विक ग्राम की भाँति उभरकर सामने आया है। जिसके परिणाम स्वरूप कई देशों की संस्कृतियां एक–दूसरे के साथ जुड़ने लगी हैं जिस कारण उनके मध्य तनाव उत्पन्न हो जाता है। वृहत रूप से नागरिकता की शिक्षा विद्यार्थियों के मध्य बहुसंस्कृति मूल्यों की स्थापना और सहयोग को बढ़ावा देती है जिससे नागरिकों के मध्य विपरीत संस्कृतियों के साथ सहयोग और सम्मान की भावना का विकास होता है।[12]
- **नागरिक गुणों ;विशेषताओंद्ध की शिक्षा–** नागरिक गुणों की प्रकृति का स्वरूप नैतिक, सत्यवान और सद्गुणी होना चाहिए। इसके अतिरिक्त वह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी करे और सरकार की गलत नीतियों तथा कार्यो के विरु(आवाज उठा कर उसे प्रभावित करने की काबलियत रखे। नागरिकता की शिक्षा भावी पीढ़ी में सद्गुणों की उपयोगिता को स्थापित कर सकती है।[13]

[10] 'NCF-2005', NCERT, P, 58-65
[11] Mudaliyar, A.L. 'Report of the Secondary Edu. Commission' Ministry of Edu. govt. of India, 1952-53, P-20-24.
[12] Banks, J.A. 'Educating Citizen in a Multicultural Society, New york : Teachers College Press, 1997.
[13] Flanagen, C.A., Cumsille, P., Gill, S., and Gallay, L.s. 'School and Community Climates and Civic Commitments: Pattern for ethnic Minority and Majority Students, Journal of Edu. Psychology, 2007, 99(2), P-422.

इसके साथ ही नागरिकता की शिक्षा और जागरुकता पर जोर देने के बावजूद सरकारें आलोचना के प्रति असहनशील हो जाती हैं।

- **मानवीय मूल्यों की शिक्षा–** मानवीय विकास के आधरभूत तत्व स्वतंत्राता, समानता, न्याय तथा ध्र्मनिरपेक्षता को नागरिकता की शिक्षा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। विद्यालयी पाठ्यचर्या में विद्यार्थियों के मध्य इनके केन्द्रीय तत्व और मानव के लिए इनके महत्व को स्पष्ट कर इसकी आवश्यकता को रेखांकित किया जा सकता है। भारत में नवीन 'पाठ्यचर्या की रूपेरखा–2005' का आधर इन्हीं मूल्यों की प्राप्ति पर आधरित है।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति से ही एक सभ्य समाज और राष्ट्र का निर्माण कर सकते है। भारत में नागरिकता की शिक्षा का परम उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और संस्थाओं के महत्व को स्थापित करना है। इसके अतिरिक्त भारतीय नागरिकों में समता, स्वतंत्राता, न्याय, बंधुत्व, ध्र्मनिरपेक्षता और बहुसंस्कृतिवाद के प्रति सम्मान, शोषण के विरु(आवाज़ उठाना, महिला विकास तथा दलित और आदिवासी संदर्भो के प्रति चेतना का निर्माण करना आवश्यक रूप से स्वीकार किया गया है जो भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकता की शिक्षा के महत्व को स्पष्ट करता है।

नागरिक शिक्षा की कमी एवं राजनीतिक ह्रास

यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की कल्पना की थी और इस पर विस्तार से अपने विचार व्यक्त किये थे। प्लेटों ने अपने ग्रंथ 'रिपब्लिक' में 'न्याय का सि(ान्त' और आदर्श राज्य की चर्चा की है एवं इसके लिए वह शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता को इंगित करते हैं। प्लेटो के अनुसार शिक्षा द्वारा ही राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, भावानात्मक और बौ(िक रूप से मजबूत बनता है जो उसे राजनीतिक कार्यो की ओर भागीदारी के लिए प्रेरित करती है। प्लेटो का उद्देश्य 'आदर्श राज्य' के लिए दार्शनिक राजा का निर्माण करना था परन्तु इस प्रक्रिया द्वारा वह अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा के महत्व को रेखांकित करता है। अरस्तु ने शिक्षा को राजनैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के एक साध्न के रूप में स्वीकार किया है। राज्य के शासकों को वह निरन्तर अध्ययन करने की सलाह देता है और कहता है कि इसके माध्यम से विचार–विमर्श को बढ़ावा मिलता है जो समाज में सहयोग और सामंजस्य स्थापित करता है। परन्तु इस स्थान पर अरस्तू शासकों को अध्ययन का महत्व समझाता है तो दूसरी ओर दास व्यवस्था को न्यायोचित ठहराता है क्योंकि दास जब अपने मालिक ;डेंजमतद्ध की सेवा करेगा और उसका सारा कार्य करेगा तभी मालिक अध्ययन कर सकेगा और शासकीय कार्यो में भागीदार हो सकेगा।

कई बार ऐसे विचार भी उत्पन्न हुए हैं कि क्या राजनीतिक ज्ञान नागरिकों के लिए आवश्यक होना चाहिए या ऐच्छिक। बहुलवादी समाज के लिए यह तर्क दिया जाता है कि सार्वजनिक तौर पर इस ज्ञान कि आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि कुछ मुख्य हित समूह नागरिक प्राथमिकताओं और हितों के रूप में प्रस्तुत किये जाते हैं। इसलिए केवल व्यक्तिगत नागरिकों को उतनी ही सूचनाएं मिले जिससे कि वे अपने प्रतिनिध्यिों का चुनाव कर सकें न कि राजनैतिक व्यक्तित्व को प्रभावित। जनसमूह अपने क्षेत्राों में निपुण होते है और उन्हें लगता है कि अन्यक्षेत्रा में निपुणता भी उनके हितो को बढ़ायेगी तो वे उससे सम्बन्ध्ति सूचनाओं को भी प्राप्त करने का प्रयास करते है। नागरिक वह सभी आवश्यक कार्य सीखते है जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है। अभिजनवादी तर्क के अनुसार जन समुदाय राजनीति को एक जिंदगी के अतिरिक्त चित्रा श्ळतमंज `पकमीवू वि सपमिश के रूप में देखता है और न ही वह उस काबिल होता है और न ही उसमें इच्छा रखता है।[14]

इस तरह यह देखा जा सकता है कि नागरिक शिक्षा की अनुउपस्थिति में राजनीतिक जागरुकता में कमी आती है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ह्रास होता है। संविधन द्वारा एक शुरुआत हुई थी किंतु सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन की गति अभी भी बहुत धीमी है। वैश्विक स्तर पर 1990 के दशक में यह देखा गया है कि वृहत रूप में नागरिकों के मध्य राजनैतिक ज्ञान का अभाव है क्योंकि व्यक्ति सूचनाओं की

---

[14] Kinder, Donald, and David O.Sears, Public Opinion and Political Action", In Handbook fo Social Psychology, Vol.2,ed. Gardner Lindzey and Elliot Aronson. New York:Random House, 1985

अनदेखी करता है किंतु उसे प्राप्त ज्ञान के आधर पर अर्थपूर्ण तथा उत्तरदायी निर्णय लेने होते है। नागरिको का यह व्यवहार नागरिक शिक्षा की कमी का प्रभाव राजनैतिक ह्रास के रूप में चिन्हित किया जा सकता है।[15] नागरिक को राजनैतिक दल, राष्ट्रीय नेता, समूह और निपुण वर्ग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी अवश्य होती है क्योंकि वह ही राजनीतिक निर्णय को स्वरूप प्रदान करते हैं। परन्तु मतदाताओं को यह नहीं पता होता है कि उनके प्रतिनिधि ने कल्याणकारी नीतियों के सन्दर्भ में क्या निर्णय लिये है या उसका क्या पक्ष है। लेकिन मतदाता अपने राजनीतिक ज्ञान और तर्क के आधर पर राजनैतिक दल के माध्यम से उन नीतियों में सटीक हस्तक्षेप कर सकता है। इसके कारण नागरिक शिक्षा का महत्व लोकतंत्रा के संदर्भ में और बढ़ जाता है।

लोकतांत्रिक निर्णयों को अर्थपूर्ण और प्राधन्य बनाने के लिए नागरिकों को राजनैतिक सन्दर्भों को समझने के काबिल ;ब्ंइसमद्ध बनना होगा ताकि वह उसका विकल्प तलाश सकें और अपना पक्ष रख सकें। सै(ान्तिक रूप से कम से कम व्यक्ति को लोकतंत्रा में शक्ति के रूप में सामूहिक निर्णयों को प्रभावित करना चाहिए और राजनैतिक रूप से इन प्रक्रियाओं के साथ जुड़े रहना चाहिए जो लोकतंत्रा की सपफलता के लिए आवश्यक है।[16]

लोकतंत्रा केवल व्यक्तिगत अध्किारों और व्यक्तियों के स्वंय हितों को पूरा करने की प्रक्रिया मात्रा नहीं है बल्कि इसे उत्तरदायित्व और सामूहिक राजनैतिक सीमाओं को निर्धरित करने के आधर पर भी स्वीकार किया जाता है। लोकतंत्रा में आवश्यक है कि व्यक्ति लोकतांत्रिक सि(ांतो और लोकतंत्रा के बुनियादी नियमों तथा खेलों को समझे। लोकतंत्रा में सभी मामलों पर सहमति की अपेक्षा नहीं की जाती। लेकिन लोकतंत्रा के महत्वपूर्ण सि(ांतो की नई परिभाषाओं ;प्दजमतचतमजंजपवदेद्ध को सहनशीलता के साथ चर्चा के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यहाँ पर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि नागरिको से लोकतांत्रिक व्यवहार की अपेक्षा की जाती है परन्तु उन्हे इस सन्दर्भ में ज्ञान और शिक्षा सही तरीके से नहीं प्रदान की जाती है। व्यवहारिक ;म्उचपतपबंससलद्ध रूप से यह देखा गया है कि शिक्षा के स्तर और लोकतांत्रिक मूल्यो को प्रोत्साहन देने के बीच गहरा सम्बन्ध है।[17] जो लोकतांत्रिक मूल्यों के ;छवतउेद्ध महत्व को समझने में नकाम हुआ है वह इन पर विश्वास करने में भी असपफल हुआ है।

भारतीय परिदृश्य में सन् 2005 से पूर्व नागरिक शिक्षा की कमी को चिन्हित किया जा सकता है। इस कारण राजनैतिक प्रक्रियाओं के परिचालन में जन समुदाय की भागीदारी निम्न थी। जिन सदस्यों ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को तैयार किया उनका विचार था कि नागरिक शास्त्रा विषय एक खास औपनिवेशिक अतीत से पनपा हुआ विषय है और इसलिए इसे बदलने की जरूरत है। पाठ्यचर्या की समिति के सदस्यों ने यह भी पहचाना कि नागरिक शास्त्रा अभी तक केवल सरकारी संस्थाओं और कार्यक्रमों का विवरण देने पर ही केन्द्रित था। यह विषय इस तरह से लिखा जाना चाहिए था जिसमें नागरिकों के मध्य आलोचनात्मक दृष्टिकोण समाहित हो। इस समझ के तहत एक नया विषय उभरा– ‘सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन’। इस नये विषय ने सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को शामिल कर अपने दायरे का विस्तार किया। इस प्रकार से पाठ्यपुस्तकों में आये परिवर्तन को हम नागरिक शिक्षा के बदले पहलुओं को राजनैतिक और सामाजिक संदर्भ में देख सकते है। राजनीति शास्त्रा नागरिक समाज को एक ऐसे क्षेत्रा के रूप में देखता है जो संवेदनशील, सवाल उठाने वाले, सोचने विचारने वाले और बदलाव लाने वाले नागरिक बनाए।[18] ‘राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2005’ की अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए ही कक्षा छः और सात की पाठ्यपुस्तकों की रचना 2006 से नवीन रूप में की गई ताकि नागरिक शिक्षा द्वारा राजनैतिक ह्रास की प्रवृत्तियों को निम्न किया जा सके। एन.सी.ई.आर.टी द्वारा प्रकाशित

---

15 Page, Benjamin I., and Robert 4. Shapiro “The Rational Public : Fifty Years of Trends in American’s Policy Preferences. Chicago : University of Chicago Press, 1992.

16 Nie, Normn H., Jane.J and kenneth, S.B. ‘Education and Democratic citizenship in America. Chicago: University of chicago Press, 1996.

17 Stouffer, 1954., Sullivan, Pierson, and Marcus, 1982; MC Closky and Zaller, 1984; Sriderman et al., 1989, 1991; Nie et al., 1996.

18 “NCF-2005” NCERT, P-59.

कक्षा छः की पाठ्यपुस्तक ''सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन–1'' का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को भारतीय राजनीतिक से परिचित कराना है ताकि सोच–विचार, छोटे समूहों में बातचीत एवं बहस जैसे विषयों को प्राथमिकता दी जा सके। इस पाठ्यपुस्तक द्वारा विद्यार्थियों के अन्दर राजनीतिक समझ के विकास हेतु 'सरकार' और 'स्थानीय प्रशासन' जैसे आम शब्दों के माध्यम से समाज में इनकी भूमिका को स्पष्ट किया गया है। सरकार क्या है?, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व कौन–कौन से है?, पंचायती राज क्या है?, गांव और नगर प्रशासन क्या है? इत्यादि ऐसे प्रश्न हैं जो नागरिकों के जीवन के साथ घनिष्ट रूप से जुड़े हुए है और इनके बारे में विद्यार्थियो के मध्य बुनियादी जानकारी का होना आवश्यक है।[19]

देश में नागरिकों के मध्य राजनीतिक प्रक्रियाओं के प्रति उदासीनता के कारण ही बालकों को उच्च प्राथमिक स्तर से ही राजनैतिक संस्थाओं, उनकी कार्यप्रणाली और स्वरूप से सम्बन्धित ज्ञान को मूल तत्व के रूप में परिभाषित किया गया जो भारतीय राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक होगा। सन् 2006 के उपरान्त निर्मित सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आज के समकालीन राष्ट्रों की आधर–शिला के रूप में चिन्हित किया गया है। कक्षा सात की पाठ्यपुस्तक में 'भारतीय लोकतंत्रा में समानता' जैसे विषयों को प्राथमिकता दी गई है। समानता, स्वतंत्राता और लोकतंत्रा का आपसी सम्बन्ध व्यक्ति की गरिमा और विकास के लिए अति आवश्यक है के रूप में विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है जो भारतीय सामाजिक परिदृश्य में नागरिकों के मध्य राजनीतिक प्रक्रियाओं तथा संस्थाओ के महत्व को इंगित करता है।[20]

सन् 2006 से पूर्व पाठ्य–पुस्तकों का स्वरूप केवल सूचनाओं पर केन्द्रित था न कि विद्यार्थियों में उन्मुकता और सरंचनात्मकता को बढ़ावा देने वाला। इसके परिणाम स्वरूप ही लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में नागरिकों की रुचि घटती चली गई। मुदालियर आयोग– ;1952–53द्ध ने लोकतांत्रिक भारत की शैक्षणिक आवश्यकता पर बल दिया और नागरिको के मध्य उन विशेषताओं के विकास पर ज़ोर दिया जो उन्हें राष्ट्रीय, अतंराष्ट्रीय, क्षेत्राीय तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास में मदद करे जिससे नव निर्मित समाज अपने राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। इसके अतिरिक्त उनमें स्मंकमतीपच ;नेतृत्वद्ध जैसे तत्वों का समावेश किया जा सके।[21]

भारतीय समाज एक नव निर्मित लोकतांत्रिक समाज है जिसके निरन्तर विकास का उत्तरदायित्व नागरिकता की शिक्षा के साथ सम्बन्धित है। नागरिकों में सहयोग, सामांजस्य तथा बन्धुत्व जैसे मानवीय मूल्यों का विकास और समानता, स्वतंत्राता और न्याय जैसे लोकतांत्रिक तत्वों का आपस में गहरा सम्बन्ध है जो राजनैतिक प्रक्रियाओं को नागरिकों से सद्गुणी व्यवहार के साथ जोड़ती है। इसलिए नागरिक शिक्षा में कमी का सीध प्रभाव राजनीतिक व्यवहार में कमी के परिणाम स्वरूप हमारे सामने आता है। भारतीय समाज ने बदलती हुई परिस्थितियों के साथ अपनी शिक्षा व्यवस्था को राजनीतिक व्यवस्था और प्रक्रियाओं को सशक्त करने के एक साध्न के रूप में अपनाया है।

भारत में नागरिकता की शिक्षा : निष्कर्षात्मक अवलोकन

भारतीय समाज एक बहुसांस्कृतिक, बहुधर्मिक, विभिन्न जातियों, सम्प्रदाय, वेशभूषा और भाषाओं का सम्मिलित स्वरूप है। इसलिए इसकी पहचान दूसरी संस्कृतियों और समाज से बिल्कुल भिन्न है जो इसे एक अद्भुत रूप प्रदान करती है। भारत में इन विभिन्नताओं का सम्मान करना और आपस में सहयोग और सामंजस्य जैसे मूल्यों का विकास करना 'नागरिक शिक्षा की आवश्यकता और इसके स्वरूप' पर निर्भर करता है। नागरिकता की शिक्षा का स्वरूप कैसा हो?, इसे किस प्रकार प्रदान किया जाये? इसके अल्पकालीन और दीर्घकालीन उद्देश्यों का निर्धरिण किस आधर पर किया जाये? इसमें राज्य की क्या भूमिका होगी? नागरिकों से किस प्रकार का व्यवहार अपेक्षित होगा? इसमें विचारधरा की क्या भूमिका होगी? इसकी विषय वस्तु का निर्धरण समकालीन परिस्थितियों के अनुरूप होगा या औपनिवेशिक द्वन्द से उपजे मूल्यों की अभिवृ(के द्वारा? इत्यादि प्रश्न इसके निर्धरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। आज समकालीन समय में

[19] 'Social and political life-1', Text book of class – VI, NCERT, 2006,p-3
[20] 'Social and political life-II', textbook of class-7, NCERT, 2006, Page-8
[21] Mudaliar, A.L. 'Report of the Secondary Edu. Commission', 1952-53, Govt. of India. p. 15-17

नागरिकों के मध्य लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और संस्थाओं के प्रति असंतोष उदासीनता में वृ(हुई है जिसके कारण समाज में आपसी संघर्ष और समानता, स्वतंत्राता, सहनशीलता और ध्र्मनिरपेक्ष जैसे मूल्यों का ह्रास हुआ है। इस स्थिति के अनेकों कारण हो सकते हैं जैसे आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और अतंराष्ट्रीय परन्तु इन सब के मध्य 'नागरिकता की शिक्षा में कमी' और इसका सही तरीके से न प्रदान किया जाना, को एक मुख्य कारण के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। नागरिकों में असंतोष की भावना, अक्रामक व्यवहार, राष्ट्रीय सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाना, एक–दूसरे के प्रति आदर में कमी आना, चुनावी प्रक्रिया में मतदान ना करना और महिलाओ के प्रति भेदभावी रवैया, इस श्रेणी की अन्य पंक्तियों में शामिल किये जा सकते है।

आज का युग लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, संस्थाओं और इनसे जुड़े मूल्यों जैसे न्याय, स्वतंत्राता तथा समानता का युग है जिसमें नागरिकों से आलोचनात्मक, सक्रिय, सचेत, नैतिक, सद्गुणी वैज्ञानिकता और तर्कवादी व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। परन्तु वास्तविक रूप में हमें इस संदर्भ में खाई नजर आती है। इस प्रकार के नागरिकों के विकास का उत्तरदायित्व 'नागरिक शिक्षा' व्यवस्था को सौंपा गया है।

भारतीय समाज में शिक्षा की परम्परा बहुत गहराई के साथ जुड़ी हुई है परन्तु नागरिकता की शिक्षा इस परम्परा का हिस्सा नहीं रही। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान 'नागरिक शिक्षा' नामक विषय का उद्भव हुआ जिसमें व्यक्ति को केवल एक विषय के रूप में माना गया ना कि एक नागरिक के रूप में। ब्रिटिश साम्राज्यवाद का उद्देश्य लोगों में अपने शासन के प्रति निष्ठा और ईमानदारी को विकसित करना था।[22] ब्रिटिश उपनिवेशवाद की भारतीयों को सभ्य बनाने योजना के तीन तत्व थे– पहला–अंग्रेजी को भाषा का माध्यम बनाना और आर्थिक क्रियाओं में उसका प्रयोग।[23], दूसरा–भारतीय इतिहास को कम महत्व देना और भारतीय समाज को विभिन्न ध्र्मो में बंटा हुआ दिखाना।[24], तीसरा–अनऔपचारिक तत्वो की परीक्षा में पुनरावृत्ति करवाना।[25] इसके अनुसार ऐसे नागरिकों का निर्माण करना था जो ब्रिटिश ताज के वपफादार बन कर रहे।

स्वतंत्राता के पश्चात् भारतीय संविधन का आधर तीन तत्वों को बनाया गया वे क्रमशः, सामाजिक न्याय, ध्र्मनिरपेक्षता एव एकल पहचान के निर्माण की आवश्यकता तथा इन तीनों तत्वों को शिक्षा व्यवस्था के उपागम के रूप में भी स्वीकारा गया। प्रधन मंत्राी पंडित जवाहर लाल नेहरू ने अल्पसंख्यक सांस्कृतिक समूह के अध्किारों को संरक्षित करने के लिए 'नागरिक शिक्षा' की उपयोगिता को चिन्हित किया है और कहा कि राज्य द्वारा उन पर कुछ भी न थोपा जाये और उनके सांस्कृतिक और कला की परम्परागत शैलियों को बढ़ावा दिया जाये जिससे एक दिशा में चलने की प्रवृत्ति का विकास को सके।[26]

भारत द्वारा सन् 1947 ई॰ में स्वतंत्राता प्राप्त की गई तब देश के नेताओं के समक्ष लोगों के अन्दर एकता के भाव का निर्माण करना एक सबसे बड़ी चुनौती थी। भारतीय संविधन द्वारा हमेशा यह प्रदर्शित किया गया कि वह एक ध्र्मनिरपेक्ष, समाहित ;पदबसनेपअमद्ध और समाजकीय आधर पर एक न्यायपूर्ण समाज है। डॉ राधकृष्णन ने राष्ट्रीय एकता की प्रथम कोंप्रफेस में कहाँ कि राष्ट्रीय एकता ईट या पत्थरों से नहीं बनती है बल्कि इसे शांतिपूर्वक व्यक्ति के हृदय और मस्तिष्क में विकसित किया जाता है। इसे प्राप्त करने की केवल एक प्रक्रिया है–वह है शैक्षणिक प्रक्रिया। शायद यह प्रक्रिया बहुत धीमी है लेकिन स्थाई जरूर है।[27]

भारतीय राष्ट्र की छवि अंग्रेजों द्वारा अपने शासन की न्योचोचितता को सही ठहराने के लिए बनाई गई। जवाहर लाल नेहरू द्वारा इसकी आलोचना की गई और भारतीय सभ्यता को एकल बताया जिसमें

[22] 'NCF-2005', NCERT, P-59

[23] Minute by T.B Macaulay, dated the 2nd Feb. 1835, retrived january 12, 2007 from www.mssu. edu/projectsouth Asia/historyMacaulay001.htm

[24] Panikkar, K.N. (2004) History Textbook in India : Narratives of Religions Nationalism. Retieved from www.sacw.net/India- History june 5, 2007

[25] Kumar, K. 'Origins of India's 'Textbook Culture', Comparative edu. Review, 32 (A), 1998, PP. 452-464.

[26] Bhattacharyya, H. 'Multiculturalism in Contemporary India, International Journal on Multicultural Societies, 5(2) , 2003, 157.

[27] Yadav, R.k. Problems of National Identity in Indian Education, Comparative Education, 1979, pp-202.

विभिन्न समूह सामूहिक भाईचारा और सहअस्तित्व के लिए साथ रहते हैं। स्वतंत्राता के बाद इसी विचार को विद्यालयी शिक्षा का भाग बनाया गया जिसमें विभिन्न समुदायों की सहअस्तित्व और शांतिपूर्ण तरीके से रहने की प्रवृत्ति को उजागर किया गया।[28]

भारत में माध्यमिक शिक्षा पर आधरित प्रथम आयोग की स्थापना ;1952–53द्ध ई॰ में की गई जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं में लोकतांत्रिाक शासन हेतु नेतृत्व की भावना को विकसित करना था। इसी आयोग की अनुसंशाओ के परिणामस्वरूप सामान्य विद्यालय ;ब्वउउवद ंबीववसद्ध की संकल्पना सामने आई ताकि देश में वर्ग, जाति और धर्मिक प्रवृत्तियों में उपस्थित नकारात्मकता को समाप्त किया जा सके और नागरिको में देश की एकता के भाव को समाहित किया जाये ख्क्कनण् बवउउपेपवदए 1966,।

1960 में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की मुलाकात हुई। इस मीटिंग में नागरिक शिक्षा को देश की एकता और अखण्डता के लिए आवश्यक माना तथा इस उद्देश्य की पूर्ती के लिए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान की महत्वता को उजागर किया जिसे नागरिकों के लिए कर्तव्य बोध् के रूप में प्रस्तुत किया गया। केन्दीय शिक्षा मंत्राालय के 1954 ई॰ ज्ञापन के अनुसार विद्यालय में दों समय सभा का आयोजन किया जायेगा जिसमे एक विद्यार्थी 'एकता की महत्तता' से सम्बन्धित विषय पर अपने विचार प्रकट करेगा जो भावी नागरिकों में नैतिकता और देश के लिए सम्मान में वृ(करेगा।

1968 ई॰ में शिक्षा पर बनी राष्ट्रीय नीती में नागरिक शिक्षा पर प्रत्यक्ष रूप से कोई विचार नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय एकीकरण समीति ने पाठ्यपुस्तको की रचना करने वाले राष्ट्रीय बोर्ड को राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक तत्वों के समावेश की सिपफारिश की जिसमें तीन उद्देश्यों को प्राप्त करने पर जोर दिया गया– प्रथम, नागरिको में भारतीय होने के सामूहिक विचार को आत्मसात् करवाना। द्वितीय, नागरिको में लोकतंत्रा के विचार को सुदृढ़ करना। तृतीय, परम्परागत समाज के स्थान पर आधुनिक विचारों का विकास करना।[29]

शिक्षा नीती 1986 ने नागरिक शिक्षा को 'विशेष्य मूल्यो' की शिक्षा देने से सम्बन्धित माना जो राष्ट्रीय विकास के उद्देश्यों से जुड़ा हो जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण और छोटे परिवारों का महत्व इत्यादि। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 और 1986 ई॰ के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 1975 और 1988 का निर्माण किया गया। इसके अनुसार शिक्षा नागरिकों में समाजिक पुर्नजागरण का एक हथियार है जिसका महत्व सबसे अध्कि है। इसके अतिरिक्त इन रूपरेखाओं ने नागरिकता की शिक्षा को अतंराष्ट्रीय समझ और सहयोग के लिए आवश्यक बताया है।[30] स्वतंत्राता के पश्चात् से ही नागरिक शास्त्रा और इतिहास की विषयु वस्तु का धै्र्य राष्ट्रीय निर्माण और ऐतिहासिक आंदोलन की व्याख्याओं तक ही सीमित रहा, परन्तु 1990 ई॰ के पश्चात् विचारकों द्वारा इसकी बहुत आलोचना की गई। नागरिक शास्त्रा द्वारा वास्तविक तथ्यों की पुर्नावृत्ति और स्मरण को अध्कि महत्व दिये जाने की भी आलोचना की गई जिसका उद्देश्य कहीं न कहीं औपनिवेशिक शासन द्वारा दिये गये ज्ञान के समरूप दिखाई पड़ता था। इसके अतिरिक्त हिन्दू–मुस्लिम विभाजन की निरन्तरता को पाठ्यपुस्तकों का हिस्सा बनाये रखा गया जिसकी 1990 के दशक में आलोचना की जाने लगी।[31]

1992 ई॰ में शिक्षा विद् यशपाल की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की गई जिसका कार्य अभिभावक–छात्राों से सम्बन्धित पाठ्यचर्या से था। इस आयोग ने 1993 में एक रिपोर्ट जारी कर कहा कि नागरिक शास्त्रा का शिक्षण भारत में निम्न स्तर का है। इसके अतिरिक्त इन्होंने इतिहास के पुनः लेखन की बात कही। इस आयोग ने यह पाया कि नागरिकता की शिक्षा के अन्तर्गत वास्तविकता और इसके आशंय

[28] Lall, M. ' The challenges for India's Education System . Asia Programme Briefing Paper 05/03 London : Chatham House, 2005, 2.

[29] Yadav, R.K. 'Problems of National Identity in Indian Education, Comparative Education, (1974), P-10(3): 201:209.

[30] Subramaniam, C.N (N.D) NCERT National Curriculum framework : A Review Retrived February 12,2007 from http//www.revolutionarydemocracy.org/NCERT.htm.

[31] Panikkar, K.N. 'History Textbooks in India : Narratives of Religions Nationalism, 2004. Retrieved from www.sacw.net/India-history, june 5, 2007

के मध्य एक बड़ी खाई है जबकि नागरिकता की शिक्षा, शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है। प्रो. यशपाल ने नागरिक शास्त्रा पाठ्यचर्या की विषय–वस्तु और तकनीक को नीरस और पिछड़ा हुआ देखा। इसलिए इसमें आने वाले दशक में बड़े और बुनियादी बदलाव को आवश्यक बताया।

सन् 2000 ई॰ में एन.डी.ए सरकार ने गुपचुप तरीके से 'राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा' को प्रस्तुत किया जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली का 'राष्ट्रीयकरण, भारतीयकरण और अध्यात्मिकीयकरण' करना था। भारतीय शिक्षा व्यवस्था मे यह प्रथम समय था जब नागरिक शास्त्रा को 'नागरिकता की शिक्षा' के रूप में स्पष्ट किया गया जिसके अनुसार विद्यार्थियों में अपनी भूमिका और उत्तरदायित्व की समझ का विकास हो सके जो लोकतांत्रिक भूमिकाओं के अनुकूल हो।[32]

नागरिकता की शिक्षा को एक स्वतंत्रा विषय तो नहीं बनाया गया परन्तु इसे मानवीय और नागरिक विकास के सम्पूर्ण मूल्यों के रूप में देखा गया। इसके मुख्य मूल्यों में अनुशासनात्मक, स्वयंनियन्त्राण, मेहनती, कर्तव्यों का बोध, उत्तरदायित्व, बंधुत्व, वृहत समझ, लोकतांत्रिक व्यवहार तथ पर्यावरण को संरक्षित बनाये रखने की समझ को नागरिकों के लिए आवश्यक बताया है। समिति ने पांच व्यक्तिगत मूल्यों को भी चिन्हित किया है वह है, सत्य, शांति, उचित व्यवहार, अंहिसा और स्नेह। इसी श्रेणी में तीन सामाजिक मूल्य भी स्पष्ट किये है जैसे श्रम का आदर करना, आत्मनिर्भरता तथा सम्पूर्ण समाज से सम्बन्धित होना। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय मूल्यों को भी आवश्यक माना गया है जैसे स्वतंत्राता संघर्ष का इतिहास, राष्ट्रीय ध्रोहर तथा संवैधनिक उत्तरदायित्व का सम्मान और पालन करना।[33] सन् 2000 ई॰ मे 'राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा' एक विवादित विषय बन कर उभरा क्योकि इसने इतिहास के परिप्रेक्ष्य में कह कर उन बिन्दुओं को बाहर निकाल दिया जो भारतीयता की तुलना में पश्चिमी ज्यादा था ख्न्चंकीलंलए 2001,। समिति के इस कदम का कड़ा विरोध किया गया और इतिहास में बिना किसी तथ्य के परिवर्तन को गलत ठहराया।

'राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2005' द्वारा सर्वप्रथम भावी नागरिकों के निर्माण के लिए विद्यालयी शिक्षा के पाठ्यक्रम को इस प्रकार का बनाया गया जो सक्रिय नागरिकों के विकास में योगदान दे सके और वह सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित हो।[34] 2006 ई॰ से इन नई पाठ्यपुस्तकों में विभिन्न प्रकार के कार्टून, विशिष्ट उदाहरण, रंगीन पृष्ट तथा अन्य प्रकार की आकर्षित क्रियाएं दी गई है ताकि विद्यार्थियों में सीखने की जिज्ञासा को प्रबल किया जा सके। इन नई पुस्तकों में ऐसे विचारों को प्रोत्साहित किया गया है जिसमें विद्यार्थी केवल सूचनाओं को ग्रहण करने वाला न बने औन न ही उन्हें उस रूप में केवल स्वीकार करे बल्कि प्रश्नों को उठाए। कक्षा 11 की पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों में संविधन के मूल्यों की समझ और उससे जुड़े नागरिक अधिकार, विभिन्न मत, स्थिति से सम्बन्धित परिचर्चा को प्रोत्साहित करती है ताकि भावी नागरिक अपनी स्थिति को समझ सके और अपने कर्तब्यों का निर्वाह कर सके।

भारत को आजाद हुए करीब 64 वर्ष हो चुके हैं लेकिन भारतीय राजनीतिक दलों ने नागरिक शिक्षा की ओर उन्मुखता बनाये रखी जिससे नागरिकों का उचित विकास नहीं हो पाया। इस कारण राजनैतिक प्रक्रिया और लोकतांत्रिक विकास का मार्ग अवरु(हुआ। नागरिकता की शिक्षा में कमीं के कारण विद्यार्थी वास्तविकता और सामाजिक संदर्भ से दूर जाता रहा जिसके परिणाम स्वरूप हमारे नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास हुआ। बल्कि इनके स्थान पर उन नीतियों को बनाना चाहिए था जो भविष्य में नेतृत्वकारी गुणों को नागरिकों में सम्मिलित कर पाएं। इन कारणों से ही आज हमारे नेता नागरिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं से अनभिज्ञ रहते है।[35] सामाजिक विज्ञान विषय का दायरा पूर्ण रूप से तथ्यों की व्याख्या तक सीमित था परन्तु आज इसका स्वरूप बदल गया है और यह सक्रिय नागरिकों के निर्माण में एक मूल विषय है।

आज भारतीय लोकतांत्रिक समाज में नागरिकता की शिक्षा को एक उपयोगी और अति–आवश्यक विषय के रूप में परिभाषित किया जा सकता हैं क्योंकि भारतीय परिस्थितियाँ बहुत जटिल और दूसरी

---

32 Press Information Bureau, 2001

33 [Parliament Committee on Human Resources Development, 1999]|

34 NCERT (2006a) Syllabus, Volume I, Elementary level New Delhi : NCERT.

35 Nayar, U.S. 'Education for social Transformation : A collective step forward, Education for social transformation, 2004, p, 50(i) : 9-14.

संस्कृतियों से कापफी भिन्न हैं। इसलिए समाज में भाईचारा, सहयोग और सामंजस्य के तत्वों को समाहित करने का कार्य यही विषय बखूबी कर सकता है। इसकी प्रासंगिकता आज और महत्वपूर्ण हो जाती है जब यह जीवन के प्रत्येक पहलू से घनिष्ट रूप से जुड़ा हुआ है और विभिन्न समस्याओं को दूर करने में यह उपयोगी साबित हो सकता है जैसे पर्यावरण और जल की कमी की समस्या, जाति और धर्म से उपजे विवाद की समस्या, अधिकार तथा कर्तव्य बोध की समस्या, लैंगिक समस्या, अनुसूचित जाति और जन जातियों की समस्या आदि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में बाधक है। नागरिक शिक्षा विषय की उपयोगिता सदा रहेगी क्योंकि सद्गुणी समाज निर्माण का यह एक उत्तम साधन है। शिक्षा के विकास के साथ साथ नागरिक शिक्षा को प्रमुख स्थान दिया जाना लोकतंत्रा को सच्चा स्वरूप देने के लिए अनिवार्य है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- National Council for Research & Training (NCERT), 'The Curriculum for Ten Year School; A Frame work', New Delhi, 1975
- NCERT,'National Curriculum for Elementrary and Secondary Edu.: A Fraemwork (NCESE), New Delhi, 1988.
- NCERT'National Curruculum Fraemework for School Education', New Delhi, 2000.
- NCERT, 'National Curriculum Framework – 2005', New Delhi, pp.48.
- Nietz, J.A. 'Old Textbooks: Spelling, Grammar, Reading, Arithmetic, Geography, American History, Civil Government, Physiology, Penmanship, Art, Music, As taught in the common Schools from Colonial days to 1900. Pittsburgh:Pittsburgh University Press. 1961.
- Heater, Derek. 'The History of Citizenship Education in England', The Curriculum Journal, 12(1): 123--130, 2001
- Eklavya. Samajik Adhyan : Kaksha 6. Bhopal: Madhya Pradesh Textbook Corporation, 1993.
- Eklavya. Samajik Adhyan : Kaksha 7. Bhopal: M.P. Text book corporation, 1994a.
- Eklavya. Samajik Adhyan : Kaksha 8. Bhopal: M.P. Text book corporation, 1994b.
- 'NCF-2005', NCERT, P, 58-65
- Mudaliyar, A.L. 'Report of the Secondary Edu. Commission' Ministry of Edu. govt. of India, 1952-53, P-20-24.
- Banks, J.A. 'Educating Citizen in a Multicultural Society, New york : Teachers College Press, 1997.
- Flanagen, C.A., Cumsille, P., Gill, S., and Gallay, L.s. 'School and Community Climates and Civic Commitments: Pattern for ethnic Minority and Majority Students, Journal of Edu. Psychology, 2007, 99(2), P-422.
- Kinder, Donald, and David O.Sears, Public Opinion and Political Action", In Handbook fo Social Psychology, Vol.2,ed. Gardner Lindzey and Elliot Aronson. New York:Random House, 1985
- Page, Benjamin I., and Robert 4. Shapiro "The Rational Public : Fifty Years of Trends in American's Policy Preferences. Chicago : University of Chicago Press, 1992.
- Nie, Normn H., Jane.J and kenneth, S.B. 'Education and Democratic citizenship in America. Chicago: University of chicago Press, 1996.
- Stouffer, 1954., Sullivan, Pierson, and Marcus, 1982; MC Closky and Zaller, 1984; Sriderman et al., 1989, 1991; Nie et al., 1996.
- "NCF-2005" NCERT, P-59.
- 'Social and political life-1', Text book of class – VI, NCERT, 2006,p-3
- 'Social and political life-II', textbook of class-7, NCERT, 2006, Page-8
- Mudaliar, A.L. 'Report of the Secondary Edu. Commission', 1952-53, Govt. of India. p. 15-17
- 'NCF-2005', NCERT, P-59
- Minute by T.B Macaulay, dated the 2nd Feb. 1835, retrived january 12, 2007 from www.mssu. edu/projectsouth Asia/historyMacaulay001.htm
- Panikkar, K.N. (2004) History Textbook in India : Narratives of Religions Nationalism. Retieved from www.sacw.net/India- History june 5, 2007
- Kumar, K. 'Origins of India's 'Textbook Culture', Comparative edu. Review, 32 (A), 1998, PP. 452-464.

- Bhattacharyya, H. 'Multiculturalism in Contemporary India, International Journal on Multicultural Societies, 5(2) , 2003, 157.
- Yadav, R.k. Problems of National Identity in Indian Education, Comparative Education, 1979, pp-202.
- Lall, M. ' The challenges for India's Education System . Asia Programme Briefing Paper 05/03 London : Chatham House, 2005, 2.
- Yadav, R.K. 'Problems of National Identity in Indian Education, Comparative Education, (1974), P-10(3): 201:209.
- Subramaniam, C.N (N.D) NCERT National Curriculum framework : A Review Retrived February 12,2007 from http//www.revolutionarydemocracy.org/NCERT.htm.
- Panikkar, K.N. 'History Textbooks in India : Narratives of Religions Nationalism, 2004. Retrieved from www.sacw.net/India-history, june 5, 2007
- Press Information Bureau, 2001
- [Parliament Committee on Human Resources Development, 1999]|
- NCERT (2006a) Syllabus, Volume I, Elementary level New Delhi : NCERT.
- Nayar, U.S. 'Education for social Transformation : A collective step forward, Education for social transformation, 2004, p, 50(i) : 9-14.

ISARA INSTITUTE OF MANAGEMENT & PROFESSIONAL STUDIES

WWW.IIMPS.IN

EARN YOUR

MBA

Accreditation & Ranking

UGC / NCTE Approved.

INFO@IIMPS.IN

011-41005174

RESEARCH GATEWAY

STOP PLAGIARISM

1 Submit your content in Word File.

2 Get report in 48 hrs.

3 *Missing content or references will be fixed.

4 Citation for your work.

5 Get accurate user friendly report.

researchgateway.in | info@researchgateway.in

+91-9205579779

AROGYAM ONLINE

Arogyam Ayurveda

Holistic Healing through herbs

100% NATURAL

PARIVARTAN PSYCHOLOGY CENTER

COLOR PSYCHOLOGY : HOW COLOR AFFECT YOUR CHILD

BLUE — Calms your Child's Mind & Body

YELLOW — Promotes Concentration, Stimulates the Memory

PINK — Evokes Empathy, makes your Child Calm

RED — Excites and energizes your Child's body

GREEN — Improves Reading speed and Comprehension

www.parivartan4u.com

Confuse about your children's future?

भारतीय भाषा, शिक्षा, साहित्य एवं शोध

ISSN 2321 – 9726

WWW.BHARTIYASHODH.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE & TECHNOLOGY

ISSN – 2250 – 1959 (0) 2348 – 9367 (P)

WWW.IRJMST.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF COMMERCE, ARTS AND SCIENCE

ISSN 2319 – 9202

WWW.CASIRJ.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES

ISSN 2277 – 9809 (0) 2348 - 9359 (P)

WWW.IRJMSH.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF SCIENCE ENGINEERING AND TECHNOLOGY

ISSN 2454-3195 (online)

WWW.RJSET.COM

INTEGRATED RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT, SCIENCE AND INNOVATION

ISSN 2582-5445

WWW.IRJMSI.COM

JOURNAL OF LEGAL STUDIES,POLITICS AND ECONOMICS RESEARCH

WWW.JLPER.COM